साप्ताहिक
Live not just breaTHE

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/16-18

दि कार्मिक पोस्ट

वर्ष : 8, अंक : 5 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 21 सितंबर 2022 से 27 सितंबर 2022 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

सख्त पर्यावरण कानून और बेहतर तकनीक का कमाल, सल्फर डाईऑक्साइड की मात्रा में तेजी से आई कमी

कोलकाता। प्रदूषण की खबरों के बीच एक अच्छी खबर। भारत के वातावरण में पिछले एक दशक के दौरान सल्फर डाईऑक्साइड की मात्रा में तेजी से कमी आई है। स्टडी में पिछले 3 दशकों के सल्फर डाईऑक्साइड के आंकड़ों का मिलान किया गया था।

सल्फर डाईऑक्साइड की मात्रा में तेजी से आई गिरावट के पीछे सख्त पर्यावरण कानून और ऐसी तकनीक का इस्तेमाल है जिससे सल्फर डाईऑक्साइड का कम उत्सर्जन हो। ये स्टडी आईआईटी खड़गपुर के सेंटर ऑफ ओशन्स, रिवर्स, एटमॉस्फियर एंड लैंड साइंस (कोरल) ने की है। संस्थान के प्रवक्ता ने बताया कि पिछले 4 दशकों (1980-2020) में पूरे भारत में सल्फर डाईऑक्साइड की मात्रा में भारी बदलाव आया है। पूरी स्टडी के दौरान पाया गया कि सल्फर डाईऑक्साइड के उत्सर्जन में थर्मल पावर प्लांट्स का योगदान 51 फीसदी और भवन निर्माण जैसी गतिविधियों का 29 फीसदी रहा है। ये बात भी सामने आई है कि भारत में 1980 से 2010 के बीच सल्फर डाईऑक्साइड की मात्रा में तेज बढ़त देखने को मिली। इसके पीछे का कारण ऊर्जा जरूरतों के लिए कोयले को जलाना और ऐसी नई तकनीक का कम इस्तेमाल रहा है जो उत्सर्जन को कम रखें। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2001-2010 की अवधि के दौरान तेजी से आर्थिक विकास ने सल्फर डाईऑक्साइड के स्तर को बढ़ाने में मदद की है। हालांकि, पिछले दशक के दौरान तकनीकी प्रगति और पर्यावरण नीतियों ने वायुमंडलीय सल्फर डाईऑक्साइड की मात्रा को कम करने में मदद की है।

अक्षय ऊर्जा उत्पादन में हुई वृद्धि

संस्थान के निदेशक प्रोफेसर वी के तिवारी ने कहा, 2010 के बाद से, भारत के अक्षय ऊर्जा उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई है क्योंकि देश ने एक सतत विकास नीति अपनाई। ऊर्जा उत्पादन में पारंपरिक कोयले से नवीकरणीय स्रोतों में बदलाव, ठोस पर्यावरण विनियमन, और प्रभावी तकनीक से देश में सल्फर डाईऑक्साइड प्रदूषण को रोकने में मदद मिलेगी, पेरिस समझौते के तहत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40 फीसदी संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करना शामिल है।

कम हो जाती है बारिश

टीम का नेतृत्व करने वाले प्रो. जयनारायण कुट्टिपूरथ का कहना है कि सल्फर डाईऑक्साइड प्रदूषणकारी है और नमी की स्थिति में ये सल्फेट के महीन कणों में परिवर्तित हो जाती है। ये महीन कण क्षेत्रीय स्तर पर बादलों के निर्माण और बारिश को प्रभावित कर सकते हैं। वातावरण में भारी मात्रा में मौजूद सल्फर डाईऑक्साइड इन्सानी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है।

जलवायु के लिए काफी महंगा है हवाई जहाज का सफर, हर साल हो रही 100 करोड़ टन सीओ2 उत्सर्जित

नई दिल्ली। यूं तो हवाई जहाजों ने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सुहाना सफर जलवायु के दृष्टिकोण से काफी महंगा है। इस पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो के स्कूल ऑफ ग्लोबल पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी द्वारा किए नए अध्ययन से पता चला है कि वैश्विक उड्डयन उद्योग से हर साल औसतन करीब 100 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड(सीओ2) उत्सर्जित हो रही है। जो जलवायु के दृष्टिकोण से एक बड़ा खतरा है।

20 वीं सदी की शुरुआत में जब राइट ब्रदर्स ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। उसके बाद से हवाई जहाजों ने पूरी दुनिया में क्रांति ला दी थी। सीमाएं सिकुड़ गई और लोगों को धरती छोटी लगने लगी। इसने दुनिया को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, लेकिन साथ ही इसकी कीमत हमें पर्यावरण और जलवायु के रुप में चुकानी पड़ रही है।

देखा जाए तो हर साल एविएशन इंडस्ट्री जितना उत्सर्जन कर रही है वो जापान द्वारा किए जा रहे कुल उत्सर्जन के बराबर है जोकि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के है। हालांकि दुनिया भर में सरकारें कारों, ट्रकों, बसों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के प्रयास कर रहीं हैं जिसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे विकल्पों को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में भी अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात करी जा रही हैं। इसके बावजूद हवाई परिवहन तकनीकी रूप से अभी भी अपने पुराने ढर्रे पर ही चल रहा है। जिसका नतीजा है कि महामारी के दौरान आए ठहराव को छोड़ दें तो इस उद्योग से होने वाला उत्सर्जन पिछले दो दशकों से हर साल 2.5 फीसदी की दर से बढ़ रहा है। इतना ही नहीं यदि इसपर ठोस कदम न उठाए गए तो आने वाले 30 वर्षों में इससे उतना उत्सर्जन होगा जितना इस उद्योग ने अपने पूरे इतिहास में नहीं किया। ऐसे में जर्नल नेचर में प्रकाशित इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने जलवायु संकट पर विमानन के बढ़ते प्रभाव को सीमित करने के लिए कड़े कदम उठाने की बात कही है। इस बारे में यूसी सैन डिएगो के स्कूल ऑफ ग्लोबल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी और इस अध्ययन से जुड़े प्रोफेसर डेविड विक्टर का कहना है कि आज सरकारें और कंपनियां जिन रणनीतियों का अनुसरण कर रही हैं वो जानी पहचानी तकनीकों पर निर्भर हैं। देखा जाए तो यह दृष्टिकोण अदूरदर्शी लगता है, क्योंकि इनमें से कई प्रौद्योगिकियां बड़े पैमाने पर काम नहीं करती हैं। उनके अनुसार बढ़ते वैश्विक तापमान पर इस उद्योग के प्रभावों को सीमित करने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। इस वास्तविकता को जितना लंबा टाला जाएगा, प्रभावी समाधान खोजना उतना ही मुश्किल होगा। गौरतलब है कि इस महीने 27 सितम्बर से 08 अक्टूबर के बीच कनाडा के मॉन्ट्रियल में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) की त्रैवार्षिक सभा आयोजित होने वाली है। इसके एजेंडे में ग्लोबल वार्मिंग पर इस उद्योग के बढ़ते प्रभाव को सीमित करना शामिल है। इस सभा में 193 देशों के मंत्री पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप, उत्सर्जन में कटौती करने के लिए उद्योग-व्यापी लक्ष्य पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे।

जलवायु परिवर्तन का कारोबार

नई दिल्ली। जलवायु परिवर्तन 21वीं सदी की प्राथमिक चुनौती बन गया है। अब जबकि कार्बन उत्सर्जन को 'नेट जीरो' करने की बात को लगभग सबने स्वीकार कर लिया है और भारी भरकम निवेश की मदद से ये व्यापक आर्थिक बदलाव पैदा करेंगे। इसकी वजह से लगभग हर बड़े उद्योग और गतिविधि (ऊर्जा से परिवहन तक और विनिर्माण से भारी उद्योग तक) पर असर होगा और सौर ऊर्जा पैनल तथा बैटरी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक चिप निर्माण तथा विशेष धातुओं तक के कारोबार को गति मिलेगी।

नया हाइड्रोजन पाइपलाइन ग्रिड मौजूदा गैस और तेल ग्रिडों के पूरक का काम कर सकता है और हर जगह चार्जिंग स्टेशन देखने को मिल सकते हैं। ऐसे किसी बड़े उद्योग के बारे में सोचना भी मुश्किल है जो इससे प्रभावित नहीं होगा। फिर चाहे हरित अमोनिया से उर्वरक बनाने की बात हो या बिना जीवाश्म ईंधन के इस्पात बनाने की। कुछ दशकों में आज की तुलना में अर्थव्यवस्था को पहचानना मुश्किल होगा। हर सप्ताह की सुर्खियां हर सप्ताह बदलाव की जरूरत सामने लाती हैं। पाकिस्तान बाढ़ में डूब रहा है और इसी असाधारण बाढ़ के कारण उसकी अर्थव्यवस्था को 9 फीसदी का नुकसान हुआ है। कहा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण नुकसान में 50 फीसदी का इजाफा हुआ है। मौसम को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है और इसकी वजह से बोआई के रुझान में तब्दीली आई है, जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ी हैं और ब्रिटेन जैसी जगहों में भारत जैसी गर्मी पड़ रही है। कई बार ऐसा लगता है मानो दुनिया ही खत्म होने को है क्योंकि हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, अंटार्कटिका के ग्लेशियर टूट रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और तमाम जीव जंतु गर्म जगहों से ठंडी जगहों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में अगर बड़ी कंपनियों की निवेश योजनाओं पर नजर डाली जाए तो सबसे बड़ी योजनाएं जलवायु परिवर्तन से संबंधित हैं। इसमें ई-कार और ई-स्कूटर से लेकर रेलवे को पूरी तरह बिजलीचालित करने तथा सौर और पवन ऊर्जा फार्म की मदद से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ाने पर जोर शामिल है। पारंपरिक कारोबारों के हरित होने के बारे में भी विचार कीजिए, तथा कम ऊर्जा के इस्तेमाल तथा कम कचरा उत्पादित करने तथा उसका अधिक से अधिक पुनर्चक्रण करने पर जोर दिया जा रहा है। सीमेंट से लेकर स्टील तक और उपभोक्ता पैकेजिंग और नौवहन (जहाजों में ऐसा पेंट करना जिससे वह पानी में आसानी से तैर सके) तक बदलाव ही बदलाव की बात है। इंसानी गतिविधियों में कार्बन का इस्तेमाल कम करने से वही होगा जो डिजिटलीकरण और संचार तथा डेटा क्रांति के चलते पहले ही घटित हो चुका है। यानी रोज की यात्राओं का अंत, आभासी बैठकें, टेलीमेडिसन और यहां तक कि दूरवर्ती शिक्षा भी। इसके अतिरिक्त बैंकिंग में तो भौतिक से आभासी तक का बदलाव हम देख ही रहे हैं। कोविड ने भी इन बदलावों को गति देने में मदद की है।

ये जीवनचक्र में दीर्घकालिक बदलाव को जन्म दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अच्छे बुनियादी ढांचे की बदौलत बड़े शहरों से दूर नई और ज्यादा अनुकूल जगहों पर रहना। ज्यादा तेज गति से चलने वाली इंटरसिटी ट्रेनों की शुरुआत से भी मदद मिलेगी। ऐसे में क्यों न कम भीड़भाड़ वाले चंडीगढ़ और जयपुर जैसे शहरों में रहा जाए और जरूरत पड़ने पर चंद घंटों का सफर करके दिल्ली पहुंच जाया जाए। मेरठ जैसे शहरों से तो एक घंटे में ही दिल्ली पहुंचा जा सकता है। संकट और अवसर के इस मेल ने सरकारों को भी कारोबारों के साथ ला दिया है जैसा कि एक संकट ही कर सकता है। हालांकि यूरोप और अन्य जगहों पर यूक्रेन संकट के कारण कार्बन पर निर्भरता बढ़ गई है। इसके बावजूद विभिन्न देशों ने उत्सर्जन लक्ष्य तय किए हैं और वांछित निवेश के लिए प्रोत्साहन और सब्सिडी की व्यवस्था की है। जानकारी के मुताबिक रिलायंस ने गुजरात सरकार से कच्छ में 1,800 वर्ग किलोमीटर जमीन मांगी है ताकि वह हरित ऊर्जा परियोजना लगा सके। यह भूभाग दिल्ली शहर से थोड़ा बड़ा है। ऐसा केवल अंबानी, अदाणी या टाटा तक सीमित नहीं है। दिग्गज सरकारी कंपनियां मसलन इंडियन ऑयल और एनटीपीसी, लार्सन ऐंड टुब्रो तथा रीन्यू पॉवर आदि भी नए अवसरों की तलाश में हैं। ओला जैसी कैब सेवा देने वाली कंपनी ने ई-स्कूटर बाजार में प्रवेश किया है और घर-घर आपूर्ति की मदद से खुदरा कारोबार में बदलाव आ ही रहा है। यकीनन कारोबार प्रभावित भी होंगे। यात्रा और स्वागत क्षेत्र, ऑफिस के पहनावे का बाजार, सिनेमाहाल और वाणिज्यिक अचल संपत्ति क्षेत्र की कंपनियों का आकार जरूर घटेगा। इनकी जगह दूरदराज की जगहों में अचल संपत्ति के अवसर बढ़ेंगे। चाहे जो भी हो भारत इस क्षेत्र में देर से आया है और उसके पास एक अनियोजित लाभ है- उसे नई चीजों के लिए रास्ता बनाने के लिए पुरानी चीजों को कम ध्वस्त करना होगा।

भाविका माहेश्वरी ने रामायण का उदाहरण देकर छात्रों को बताई आगे बढ़ने की राह

केवट की तरह बड़ा लक्ष्य रखना चाहिए

औबेदुल्लागंज। जब भगवान राम गंगा पार करने के लिए घाट पर पहुंचे और राम ने गंगा पार करने के बदले केवट को अंगूठी देना चाही, तो केवट ने कहा कि आज मैंने आपको नदी पार कराई है, जब मैं आपके द्वार आऊं, तो आप भवसागर पार करा देना। इसलिए हम बच्चों को भी बड़ा लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना चाहिए। यह बात गुजरात की १३ साल की बाल कथावाचक, प्रेरक वक्ता और लेखिका भाविका माहेश्वरी ने छात्रों से कही।

भाविका ने कहा जब भरत ने हनुमान को पर्वत ले जाते समय घायल कर दिया, तो भरत ने तत्काल हनुमान से माफी मांगी थी। उन्होंने कहा गलती पर माफी मांगने से छोटे नहीं बड़े बनते है। उन्होंने कहा कि रामायण में सात कांड होते है और छटवें पर सुंदरकांड आता है। क्योंकि पांचवे पर किस्किंदा कांड में ज्यादा सोच विचार होता है और सातवें में सोच विचार कम। इस कार्यक्रम को गोल्बल स्कूल ऑफ एक्सिलेंस औबेदुल्लागंज में सेन्स्ड संस्था ने करवाया है।

सेन्सड संस्था ने अपना स्थापना दिवस एक शाम शहीदों के नाम समर्पित कर मनाया

औबेदुल्लागंज। संस्कृति संचालनालय के सहयोग से सेन्स्ड संस्था का स्थापना दिवस मधुर देशभक्ति गीतों से वीर शहीदों को याद कर मनाया गया जिसमे संस्था को स्कूल ग्लोबल स्कूल ऑफ एक्सलेंस के विद्यार्थियों द्वारा सुरीले देशभक्ति गीतों और धुनों का अदभुत प्रदर्शन किया गया और सेन्स्ड संस्था के विभिन्न कोर्सों में प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थियों ने सीखे गए नृत्य से विभिन्न प्रस्तुतियां दी। सेन्स्ड संस्था समाज हित में कार्य करने के लिए वचन बद्ध है जिससे देश के विकास में योगदान दे सके और हर जन देश के विकास में बराबर का भागीदार हो। सेन्स्ड संस्था की सेक्रेटरी डॉ. सोनल मेहता ने अपने संबोधन में कहा की संस्था वटवृक्ष की शाखाओं की तरह फैले जिससे समाज के हर वर्ग का विकास और उन्नति की राह आसान हो जाए। ग्लोबल स्कूल की प्राचार्य ललित जयमोन ने बताया कि सेन्स्ड संस्था १२ वर्ष से निरंतर सेवा शिक्षा और सहयोग का कार्य कर रही है।

हैदराबाद-इंदौर सहित 92 शहरों में संतोषजनक रही हवा

इंदौर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 21 सितम्बर 2022 को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 161 शहरों में से 52 में हवा बेहतर रही, जबकि 92 शहरों की श्रेणी संतोषजनक, 17 में मध्यम रही। यदि दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 109 दर्ज किया गया है। दिल्ली के अलावा फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 90, गाजियाबाद में 106, गुरुग्राम में 136, नोएडा में 96 पर पहुंच गया है। देश के अन्य प्रमुख शहरों से जुड़े आंकड़ों को देखें तो मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 53 दर्ज किया गया, जो प्रदूषण के संतोषजनक स्तर को दर्शाता है। जबकि कोलकाता में यह इंडेक्स 37, चेन्नई में 85, बैंगलोर में 60, हैदराबाद में 65, जयपुर में 78 और पटना में 68 दर्ज किया गया।

यूजीसी ने न्याय तक पहुंच और पर्यावरण कानून पर दो एमओओसी कोर्स की घोषणा की

नयी दिल्ली, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने न्याय तक पहुंच और पर्यावरण कानून विषय पर दो और स्नातकोत्तर वृहद मुक्त ऑनलाइन कोर्स (एमओओसी) की घोषणा की जिन्हें स्वयं पोर्टल पर आठ भारतीय भाषाओं में जारी किया गया है। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने ट्वीट कर यह जानकारी दी । . यूजीसी के 8 अगस्त 2022 को 'यूजीसी ई संसाधन पोर्टल' प्रारंभ करने एवं उसके एकीकरण की पहल को लेकर जारी पत्र की बातों को आगे बढ़ाते हुए आयोग ने दो और 'एमओओसी कोर्स' को स्वयं पोर्टल एवं यूजीसी ई संसाधन पोर्टल पर अपलोड किया है जिसमें एक्सेस टू जस्टिस (न्याय तक पहुंच) और पर्यावरण कानून शामिल हैं ।.

खेतों में पराली जलाने को रोकने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने दी बड़ी जानकारी

नई दिल्ली- दिल्ली सरकार खेतों में पराली जलाने की घटनाएं रोकने एवं 5,000 एकड़ बासमती और गैर-बासमती खेती वाली भूमि पर जैव-अपघटक (बायो-डिकम्पोजर) का छिड़काव करेगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। राय ने यह भी कहा कि पंजाब में 5,000 एकड़ या 2,023 हेक्टेयर भूमि पर जैव-अपघटक का छिड़काव प्रायोगिक आधार पर किया जाएगा। जैव-अपघटक एक प्रकार का तरल पदार्थ है, जो पराली को 15 से 20 दिनों में खाद में बदल सकता है। राय ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली सरकार इस साल 5,000 एकड़ बासमती और गैर-बासमती खेती वाली भूमि पर जैव-अपघटक का मुफ्त छिड़काव करेगी।

रेडिएशन के खतरे के बीच काम कर रहे हैं दुनिया में 2.4 करोड़ श्रमिक....

न्यूयार्क विश्वभर में 2.4 करोड़ श्रमिक विकिरिण (रेडिएशन) प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यह बहुत ही भयावह स्थिति है। इस भयावह स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ मिलकर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है।

यह सम्मेलन स्विट्जरलैंड सरकार द्वारा आयोजित किया गया है। सम्मेलन में दुनिया भर के 500 से अधिक विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। ये विशेषज्ञ विकिरण से श्रमिकों की सुरक्षा को और मजबूती प्रदान करने के लिए सूचनाओं और अपने-अपने अनुभवों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। यह आयोजन गत पांच सितंबर से शुरू हुआ है और आगामी नौ सितंबर तक चलेगा। सम्मेलन में पिछले बीस सालों में श्रमिकों पर हुए विकिरण के प्रभाव के अंतरराष्ट्रीय मानकों और सुरक्षा के लिए की गई सिफारिशों की समीक्षा भी की जाएगी। साथ ही एक बेहतर वैश्विक पेशेवर विकिरण सुरक्षा प्रणाली की पहचान करेगी, ताकि श्रमिकों पर विकिरण के प्रभाव को खत्म किया जा सके। ध्यान रहे कि विकिरण का जोखिम आमतौर पर परमाणु क्षेत्र में काम करने वाले या रेडियोधर्मी स्रोतों से निपटने वालों से जुड़ा होता है। इसके अलावा अन्य व्यवसायों में काम करने वाले, जैसे कि खनिक, एयरक्रू, शोधकर्ता और स्वास्थ्य कर्मी भी पर्याप्त उपाय नहीं किए जाने पर गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में दुर्घटनाएं न केवल श्रमिकों के लिए बल्कि स्थानीय समुदायों और पर्यावरण के लिए भी विनाशकारी प्रभाव डाल सकती है। इसलिए सख्त नियम और नियंत्रण के कठोर उपायों को लागू करने की जरूरत है। इन सभी विषयों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाएगा। सम्मेलन के उप-महानिदेशक विक वान वुरेन ने कहा कि 1919 में श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा आईएलओ की स्थापना के बाद से यह एक संवैधानिक उद्देश्य रहा है। हम अभी भी इस उद्देश्य से बहुत दूर हैं। वह कहते हैं कि यह सम्मेलन ज्ञान और अनुभव का आदान-प्रदान करने के लिए एक उत्कृष्ट अवसर के रूप में काम करेगा और सभी उद्योगों और देशों में श्रमिकों के विकिरण सुरक्षा को बढ़ाने और काम के माहौल को सुरक्षित व स्वस्थ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। जून 1960 में हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में विकिरण संरक्षण की सिफारिश नंबर 115 और सिफारिश नंबर 114 को स्वीकार किया गया था। सम्मेलन के दौरान बनाए गए इन प्रावधानों को आईएलओ के प्रत्येक सदस्य ने पुष्टि की थी और इन प्रावधानों को अपने-अपने देशों में कानूनों और अन्य उपयुक्त नियमों के माध्यम से प्रभावी रूप से लागू करने की बात स्वीकारी थी। यह एकमात्र अंतरराष्ट्रीय कानूनी साधन है जो विकिरण के खिलाफ श्रमिकों की सुरक्षा प्रदान करता है। इस सम्मलेन में लिए गए निर्णयों को 50 देशों द्वारा पुष्टि की गई थी।

तंबाकू के सेवन से विश्व में हर साल 70 लाख से अधिक लोगों की मौत, पर्यावरण के लिए भी हानिकारक

नई दिल्ली तंबाकू मानव स्वास्थ्य के लिए तो बेहद खतरनाक है, लेकिन इसकी खेती भी पर्यावरण के लिए उतनी ही विनाशकारी है। तमाम असाध्य रोग देने वाले तंबाकू की खेती से मृदा के अनुर्वर होने, वनोन्मूलन, वायु प्रदूषण और जैव विविधता के नष्ट होने का खतरा भी बढ़ जाता है। यानी तंबाकू मानव संसाधन और राष्ट्रीय आय के साथ-साथ बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकीय क्षति के लिए उत्तरदायी है।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, विश्व में करीब 125 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। इनमें 15 वर्ष से अधिक आयु के 27 करोड़ भारतीय भी शामिल हैं। चीन के बाद भारत तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक देश भी है। तंबाकू के सेवन से विश्व में हर साल 70 लाख से अधिक लोगों की मौत होती है। भारत में तंबाकू से मरने वालों की संख्या साढ़े तेरह लाख प्रतिवर्ष है। एक उत्पाद के रूप में तंबाकू बहुत अहितकारी है। खेतों में इसे उपजाने से लेकर उसके वितरण, खपत और उसके पश्चात कचरे के रूप में यह पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है। तंबाकू की खेती को आर्थिक समृद्धि और गरीबी दूर करने का जरिया माना जाता है, लेकिन हर साल दो लाख हेक्टेयर जंगलों को तंबाकू की खेती के लिए समतल किया जाता है। यह 60 करोड़ पेड़ों के नष्ट होने के बराबर है। यही नहीं, इसकी खेती के लिए बड़ी मात्रा में पानी और ऊर्जा की भी खपत होती है। तंबाकू उत्पाद अपनी निर्माण प्रक्रिया और उसके पश्चात भी बड़े पैमाने पर कार्बन डाईआक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। यह उद्योग हर साल आठ करोड़ टन कार्बन डाईआक्साइड का उत्सर्जन करता है। यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए यह काफी हद तक जिम्मेदार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, तंबाकू की खेती में लगे श्रमिक रोजाना 50 सिगरेट के बराबर निकोटिन अवशोषित कर लेते हैं। सिगरेट के इस्तेमाल के बाद जब उसके फिल्टर को फेंका जाता है, तो उसमें मौजूद माइक्रोप्लास्टिक के अंश टूट-टूटकर मिट्टी में मिल जाते हैं, हवा में तैरते हैं या जलस्रोतों में घुल जाते हैं। इसके खतरनाक रसायन बड़ी आसानी से वहा, खाद्य पदार्थों और पेयजल के जरिये मानव शरीर में पहुंचकर आनुवांशिकी परिवर्तन, मस्तिष्क विकास और श्वसन तंत्र की समस्या उत्पन्न करते हैं। हर साल करीब साढ़े चार ट्रिलियन सिगरेट फिल्टर समुद्रों, नदियों, सड़कों और पार्कों को प्रदूषित करते हैं। स्वाभाविक है कि उनकी सफाई में अतिरिक्त मानव श्रम की जरूरत पड़ती है। इसके अवशेष इन स्थानों के सौंदर्य पर भी ग्रहण लगाते हैं। ऐसे में आवश्यक है कि ऐसे उत्पादों के प्रयोग को हतोत्साहित किया जाए। यह मानव स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह है।

देश को सतत विकास के साथ-साथ पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण की सुरक्षा की भी आवश्यकता है- नितिन गडकरी

नयी दिल्ली सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश को सतत विकास के साथ-साथ पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण की सुरक्षा की भी आवश्यकता है। श्री गडकरी आज नई दिल्ली में जलवायु उद्देश्यों पर आधारित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत, चौदह से सोलह लाख करोड़ रुपये का जीवाश्म ईंधन आयात करता है जो कि देश पर पर्यावरणीय बोझ के साथ-साथ आर्थिक भार भी है।

श्री गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' दृष्टिकोण को साकार करने के लिए आयात में कमी लाने के विकल्प खोजना वर्तमान समय की आवश्यकता है। श्री गडकरी ने 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए चार स्तंभों को महत्वपूर्ण बताया। ये सिद्ध प्रौद्योगिकी, आर्थिक व्यवहार्यता, कच्चे माल की उपलब्धता और उत्पाद की विपणन क्षमता के रूप में मौजूद हैं। श्री गडकरी ने अनुसंधान संगठनों से अपशिष्ट सामग्री प्रबंधन और कार्बन उत्सर्जन से निपटने के लिए शत-प्रतिशत नए नवाचारों का पता लगाने का भी आग्रह किया।

प्रधानमंत्री राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को करेंगे संबोधित

नयी दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात के एकता नगर में आयोजित होने वाले विभिन्न राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, मोदी इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वहां उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे।.

अमृत सरोवर एवं जल स्त्रोतों की सफाई की गई एवं जल संरक्षण के लिए घर-घर चलाया गया जागरूकता अभियान

इंदौर गौरव रणदिवे ने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पार्टी सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है इस ही के अंतर्गत आज सेवा पखवाड़े के चौथे दिन भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा वार्ड स्तर पर विभिन्न अमृत सरोवर एवं जल स्त्रोतों जैसे कुएं ,तालाब बावड़ीयो आदि की साफ सफाई की गई साथ ही घर-घर जाकर जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक किया ।

साथ ही प्रकोष्ठ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन चमेली देवी अग्रवाल रेड क्रॉस ब्लड बैंक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर छावनी पर किया गया भाजपा खेल प्रकोष्ठ के लगभग 71 सदस्यों ने रक्तदान किया इस अवसर पर विश्वामित्र पुरस्कार , विक्रम अवार्ड , एकलव्य अवार्ड से सम्मानित तथा शस्त्र कला में प्रथम आए खिलाड़ियों ने भी रक्तदान किया इस अवसर पर भाजपा खेल प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश के संयोजक श्रवण मिश्रा जी जो भोपाल से पधारे थे ने रक्त दाताओं में ऊर्जा का संचार करते हुए कहा की रक्तदान करने से हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ती है तथा आम आदमी से ज्यादा शक्ति खिलाड़ियों में होती है उनको रक्तदान जरूर करना चाहिए । इस अवसर पर नगर अध्यक्ष श्री गौरव रणदिवे, विधायक श्री रमेश मेंदोला ,श्री आकाश विजयवर्गीय, श्रीमती मालिनी गौड़, श्री महेंद्र हार्डिया, पूर्व विधायक श्री सुदर्शन गुप्ता,वरिष्ठ भाजपा नेता श्री मधु वर्मा, सभी वार्डों के पार्षद गण भाजपा खेल प्रकोष्ठ इंदौर नगर के संयोजक मान सिंह यादव , सह संयोजक वीरेंद्र पवार ,राजेश यादव ,दीपक राजोरे ,अजय राठौर, मिथिलेश कैमरे, दीपक बैरागी और खेल प्रकोष्ठ के सभी सदस्य उपस्थित थे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश संयोजक खेल प्रकोष्ठ के श्री श्रवण मिश्रा , खेल प्रकोष्ठ इंदौर नगर के प्रभारी राजू सिंह चौहान, नगर महामंत्री श्रीमती सविता अखंड ,झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ नगर संयोजक श्री अनिल शर्मा ,युवा मोर्चा नगर मंत्री राहुल ठाकुर ,सनी तिवारी , प्रेम विजयवर्गीय आदि के साथ सैकड़ों युवा खिलाड़ी उपस्थित थे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008